



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
 भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
 प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940

No. 270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

(बंतिम जांच परिणाम)

विषय: चीन जन. गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोइंड्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में
 मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 7/13/2018-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनयम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 जिसे यहां आगे 'नियमावली अथवा'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए एलॉय स्टील प्रोड्यूशर एसो. आफ इण्डिया ('ए एस पी ए') (जिसे यहां आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष मध्यावधि समीक्षा ('एम टी आर') जांच के लिए आवेदन पत्र दायर किया था।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. जबकि, प्राधिकारी ने मैसर्स एच ई जी लिमि. और मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में 20/05/2013 की संख्या 14/02/2013 – डी जी ए डी द्वारा मूल जांच की शुरुआत की थी। जांच परिणाम चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सभी व्यासों के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोइंड्स' (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 19/11/2014 की अधिसूचना संख्या 14/02/2013 – डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित किए गए थे और केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13/02/2015 की अधिसूचना संख्या 4/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
3. जबकि, एलॉय स्टील प्रोड्यूशर एसो. आफ इण्डिया ने आयातकों की ओर से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के लिए सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन

पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के अनुसार अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र दायर किया है। आवेदक द्वारा यह दावा किया है कि मूल जांच की जांचावधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया है, जिसमें स्थिति ऐसी हो गई है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की अब आवश्यकता नहीं है।

ख. जांच की शुरुआत

4. जबकि, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1क) में यह अपेक्षा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी पहल पर अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार, जो ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सोचना प्रस्तुत करे, जहां आवश्यक हो पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और जहां निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से पर्याप्त समयावधि समाप्त हो गई हो तथा ऐसी समीक्षा पर निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी वापसी के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करेंगे, जहां वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना नहीं है, यदि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है अथवा उसमें अंतर किया जाता है और इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है।
5. ऐसी समीक्षा की आवश्यकता सिद्ध करते हुए और लागू उपाय की समीक्षा की आवश्यकता होने के लिए परिवर्तित परिस्थितियां दर्शाते हुए आवेदक द्वारा दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 04 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/13/2018 – डी जी ए डी द्वारा पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 4/2015 – सीमा शुल्क द्वारा लगाये गये निश्चयात्मक शुल्क और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित 19 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/02/2013 – डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम के संबंध में मध्यावधि समीक्षा (एम टी आर) जांच शुरू की।

ग. प्रक्रिया

6. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है :

 - i. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातिकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों को 04 अप्रैल, 2018 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रतियां भेजी। सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार और आंकड़े उपलब्ध करायें। निर्यातिकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातिकों/ उत्पादकों की सूची सहित भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को भी भेजी गई, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे संबद्ध देश के निर्यातिकों/ उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दें।
 - ii. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातिकों को एम टी आर की शुरुआत संबंधी सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) तथा 6(4) के अनुसार पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातिक प्रश्नावलियां भेजीं।

 - क. मैसर्स फूशन कॉर्बन कं. लिमि.,
 - ख. मैसर्स जिलिन कॉर्बन इम्पो. एंड एक्सपो. कम्पनी,
 - ग. मैसर्स कैफेंग कॉर्बन कं. लिमि.,
 - घ. मैसर्स फांगडा कार्बन न्यू मेटेरियल कं. लिमि.,
 - ड. मैसर्स सिनोस्टील ज़ेजियांग कं. लिमि.,
 - च. मैसर्स सिनोस्टील जिलिन कॉर्बन कं. लिमि.
 - छ. मैसर्स लिंग्यी काउंटी लूबेई कॉर्बन कं. लिमि.,
 - ज. मैसर्स शांगडोंग बेसन कॉर्बन प्लांट,
 - झ. मैसर्स अनसीन मेटालूर्गी ग्रुप कं., लिमि.,

ज. मैसर्स ननटॉग यांगजी कॉर्बन कं. लिमि.,

ट. मैसर्स सिचुंग गुअगधन सिदा कॉर्बन कं. लिमि.,

ठ. मैसर्स फूशंग ओरियंटल कॉर्बन कं. लिमि.,

ड. मैसर्स लिआयांग कॉर्बन कं. लिमि.,

ढ. मैसर्स लिंगवर्ड हॉगफेंग कॉर्बन प्रॉक्टस कं. लिमि.,

ण. मैसर्स जिन्नई कॉर्बन (एच के) कं. लिमि.,

त. मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कं. लिमि.,

थ. मैसर्स सी आई एम एम डॉगवर्ड इंडियान्स कॉर्बन कं. लिमि.,

iii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समयावधि 15/06/2018 तक बढ़ाई।

iv. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातिक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिया है।

क. मैसर्स लिआयांग कॉर्बन कं. लिमि. (उत्पादक) मैसर्स जिन्नई कॉर्बन (एच के) कं. लिमि., हॉगकॉंग (निर्यातिक)

ख. मैसर्सहेफेर्ड कॉर्बन कं. लिमि., चीन जन. गण. (उत्पादक) एवं मैसर्स फंगडा कॉर्बन न्यू मेटेरियल कं. लिमि., चीन जन. गण. (निर्यातिक एवं उत्पादक)

ग. मैसर्स फूशंग ओरियंटल कॉर्बन कं. लिमि., (उत्पादक), चीन जन. गण. एवं मैसर्स अनसीन मेटालुर्गियी ग्रुप कं. लिमि. (निर्यातिक) चीन जन. गण.

घ. मैसर्स डांगडॉग सिंगसिंग कॉर्बन कं., लिमि., (उत्पादक) चीन जन. गण., मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कं., लिमि., (निर्यातिक) चीन जन. गण. एवं मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चीन लिमिटेड (निर्यातिक), हॉग कॉंग,

v. सी सी पी आई टी / सी सी ओ आई सी के इंटरप्राइज राइट्स प्रोटेक्शन सेंटर ने केवल लिखित अनुरोध दायर किये हैं।

vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित जात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को भी पत्र भेजे गए थे :

क. सेल, एलॉय स्टील प्लांट

ख. सेल, भिलाई स्टील प्लांट

ग. सेल, बोकारो स्टील प्लांट

घ. सेल, राउरकेला स्टील प्लांट

ड. सेल, दुर्गापुर स्टील प्लांट

च. सेल, विश्ववेसवराय आयरन एंड स्टील प्लांट

छ. भूषण स्टील लिमि.

ज. सनफल्या आयरन एंड स्टील कं. लिमि.

झ. जिंदल स्टील एंड पावर लिमि.

ज. जिंदल स्टेनलैस लिमि.

ट. लॉयड स्टील इंड. लिमि.

ठ. मुकंद लिमि.

ड. जे एस डब्ल्यू इस्पात स्टील

ढ. आई एस एम टी लिमिटेड

ण. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

vii. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/ आयातकों ने प्रयोक्ता/ आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किये हैं :

क. सारलोहा एड्वास मेटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. आर एम जी एलॉच स्टील लिमि.

ग. वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमि.

घ. जे एस डब्ल्यू स्टील लिमि.

viii. आवश्यक सूचना और उत्तर के लिए मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. और मैसर्स एच ई जी लिमि., मूल जांच में घरेलू उद्योग होने वाले भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात घरेलू उत्पादकों को पत्र भेजे गए थे। मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स एच ई जी लिमि. ने कोई उत्तर, संबद्ध जांच में टिप्पणियां अथवा संबंधित आकड़े दायर नहीं किये। मैसर्स एच ई जी लिमि. ने दिनांक 05/06/2018 के पत्र द्वारा अनुरोध किया कि उन्होंने समीक्षा का विरोध नहीं किया है और निदेशालय मांग/ आपूर्ति की स्थिति तथा चीन में घरेलू कीमतों बनाम उनकी निर्यात कीमतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दृष्टिकोण ले सकता है। मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. ने दिनांक 09/06/2018 के पत्र द्वारा यह अनुरोध किया कि इस मामले में भारत और चीन में चीनी उत्पादों की समकालीन कीमत और अन्य संगत/ संबंधित मामलों का संज्ञान लेने के बाद उपर्युक्त रूप से निर्णय लिया जाये।

ix. जांच 1 अप्रैल, 2017 से शुरू करके 31 मार्च, 2018 (जांच की अवधि) की अवधि के लिए की गई थी तथापि, क्षति की जांच अप्रैल 2014 – मार्च 2015, अप्रैल 2015 – मार्च 2016, अप्रैल 2016 – मार्च 2017 तथा जांच की अवधि के लिए की जानी थी।

x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 17 जुलाई, 2018 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया, जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दायर करें। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा जहां भी संगत माना गया है इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

xi. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त व अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराये।

xiii. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने इसे अस्वीकार किया है अथवा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किया है।

xiv. जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों और दी गई सूचना, जहां तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई है, पर प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त रूप से विचार किया गया है।

xv. प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणियां देने के लिए 7/8/2018 तक का समय देते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण 1/8/2018 को जारी किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर समुचित रूप से विचार किया है।

xvi. अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में '***' गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के तहत स्वीकार की गई सूचना को दर्शाता है।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोइंस ऑफ आल डाईमीटर' है। उत्पाद क्षेत्र मूल जांच में परिभाषित किये गये अनुसार ही है।

8. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोइंस का मुख्य प्रकार्य इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज से भरकर भट्टियों में स्टील की मेलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाना होता है। इस्पात निर्माण की पद्धति गौण इस्पात निर्माण के रूप में भी जानी जाती है। इलेक्ट्रोइंस का प्रयोग करंट ले जाने वाले कंडक्टरों के रूप में आर्क फर्नेस में किया जाता है और बहुत ही उच्च दर की विद्युत आपूर्ति ले जाने के लिए अपेक्षित होता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोइंस को व्यापक रूप से अल्ट्रा हाई पावर (यू एच पी) तथा अन्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जिनमें उच्च पावर ग्रेड (एच पी जी) और नार्मल पावर ग्रेड (एन पी जी) शामिल होते हैं। तदनुसार, उनमें इतना उच्च करंट और विद्युत लेने के लिए सक्षम गुणधर्म होने अपेक्षित हैं।

9. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष 8545 के तहत वर्गीकृत है और प्राथमिक रूप से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद संख्या 85451100 तथा 85451900 के तहत आयात किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

10. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा समक्ष सामान भारत में आयात किये जा रहे संबद्ध सामानों के समान है। दोनों की विशेषताएं भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्राचोगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय हैं। वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए नियमों के तहत उन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

11. चूंकि, आवेदक के सिवाय किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। अतः वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र वहीं रहता है जो मूल जाच में है।

इ. घरेलू उद्योग और आधार

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ब्र) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियंत्रकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

13. मूल जांच के दौरान मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स एच इ जी लिमि. घरेलू उद्योग बने हुए थे। इस स्थिति में वर्तमान जांच की जांचा अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं है और इसके विपरीत किसी हितबद्ध पक्षकारने कोई अनुरोध नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति के मददेनर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग वर्तमान एम पी आर जांच में नियम 2(ब्र) के अभिप्राय से मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स एच इ जी लिमि. घरेलू उद्योग तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करते हैं।

इ. पाटनमार्जिन एवं क्षति मार्जिन

14. सदस्य आयातकों की ओर एसो. द्वारा यह दावा करते हुए आवेदन पत्र दायर किया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है तथा क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि राजस्व लाभ और नियोजित पूँजी पर आय (आर ओ सी ई) के संदर्भ में घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग पिछले कुछ वर्षों में संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का निर्यात करता रहा है और भारतीय बाजार की मांग की उपेक्षा कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में संबद्ध सामानों की कमी हो गई है। भारत में घरेलू उत्पादकों ने न तो आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों के संबंध में न कोई चुनौती दी है और न ही कोई लागत संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

15. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के उत्पादकों/ निर्यातकों के निम्नलिखित समूहों ने इस मध्याविधि समीक्षा में प्रश्नावली के उत्तर दायर किये हैं।

क. मैसर्स लिआयांग कॉर्बन कं. लिमि. (उत्पादक) मैसर्स जिन्नई कॉर्बन (एच के) कं. लिमि., हॉगकॉंग (निर्यातक)

ख. मैसर्सहेफेर्इ कॉर्बन कं. लिमि., चीन जन. गण. (उत्पादक) एवं मैसर्स फंगडा कॉर्बन न्यू मेटेरियल कं. लिमि., चीन जन. गण. (निर्यातक एवं उत्पादक)

ग. मैसर्स फूशंग ओरियंटल कॉर्बन कं. लिमि., (उत्पादक), चीन जन. गण. एवं मैसर्स अनसीन मेटालुर्गी ग्रुप कं. लिमि. (निर्यातक) चीन जन. गण.

घ. मैसर्स डांगडांग सिंगसिंग कॉर्बन कं. लिमि., (उत्पादक) चीन जन. गण., मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कं. लिमि., (निर्यातक) चीन जन. गण. एवं मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चीन लिमिटेड (निर्यातक), हॉग कॉंग,

घ. सामान्य मूल्य

16. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों यथा – मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स एच ई जी लिमि., जो मूल जांच में घेरेलू उद्योग थे, ने कोई उत्तर, अति संबंधी आंकड़े अथवा संबद्ध जांच में टिप्पणियां दायर नहीं की हैं और न ही जांच का विरोध किया है तथापि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किये हैं, जिसमें उन्होंने सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत का दावा किया है। किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा नहीं किया है। उत्तरों में प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन नहीं किया गया है तथापि, सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के आधार पर पाठन मार्जिन जैसा कि उत्पादक निर्यातकों ने अपने उत्तर में दावा किया है, के ब्यौरे निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिये गये हैं।

II. निर्यात कीमत

क. मैसर्स लिआयांग कॉर्बन कं. लिमि. (उत्पादक) मैसर्स जिन्नई कॉर्बन (एच के) कं. लिमि., हॉगकॉंग (निर्यातक)

17. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार मैसर्स लिआयांग कॉर्बन कं. लिमि. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उन्होंने अपनी संबंधित व्यापारिक कम्पनी मैसर्स जिन्नई कॉर्बन (एच के) कं. लिमि., हॉगकॉंग के माध्यम ही भारत को निर्यात किया है। उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन का निर्यात किया है। अंतर्देशीय परिवहन (एफ ओ बी तक), समुद्री भाड़ा और बीमा और पत्तन तथा अन्य संबंधित व्यय के निमित समायोजन का दावा किया गया है। उत्तर में दावा किये गये अनुसार कारखानागत स्तर पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

ख. मैसर्स हेफेरिंग कॉर्बन कं. लिमि., चीन जन. गण. (उत्पादक) एवं मैसर्स फंगडा कॉर्बन न्यू मेटेरियल कं. लिमि., चीन जन. गण. (निर्यातक एवं उत्पादक)

18. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार मैसर्स फंगडा कॉर्बन न्यू मेटेरियल कं. लिमि. चीन जन. गण. ('फंगडा कार्बन') विभिन्न ग्रेडों यथा – आर पी, एच पी, एच डी, एस एच पी, यू एच पी, ग्रेडों के ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस का उत्पादक है। कंपनी ने जांच की अवधि में भारत को *** मी. टन निर्यात सूचित किया है। इन निर्यातों में से कंपनी ने ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस के *** मी. टन का निर्यात किया, जिसका विनिर्माण उनके द्वारा किया जाता है और शेष *** मी. टन का विनिर्माण मैसर्स हेफेरिंग कॉर्बन कं. लिमि. द्वारा किया गया था। भारत को बिक्री सी आई एफ आधार पर की गई थी। अंतर्देशीय भाड़ा, सार संभाल प्रभार, समुद्री भाड़ा के निमित समायोजन का दावा किया गया है। उत्तर में दावा किये गये अनुसार कारखानागत स्तर पर भारत को निर्यात के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ग. मैसर्स फूशंग ओरियंटल कॉर्बन कं. लिमि., (उत्पादक) चीन जन. गण. एवं मैसर्स अनसीन मेटालुर्गी ग्रुप कं. लिमि. (निर्यातक) चीन जन. गण.

19. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार मैसर्स फूशंग ओरियंटल कार्बन कं. लिमि. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है। जांच की अवधि के दौरान उसके उत्पादों का निर्यात मैसर्स अनसीन मेटालुर्गी ग्रुप कं. लिमि. के माध्यम से किया गया है जो कि एक मात्र व्यापारिक कंपनी है। मैसर्स अनसीन मेटालुर्गी ग्रुप कं. लिमि. ने अलग से उत्तर दायर किये हैं। उन्होंने जांच की अवधि के दौरान *** मी. टन का निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों ऋण लागत, और वैट के निमित समायोजन का दावा किया गया है। उत्तर में दावा किये गये अनुसार कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

घ. मैसर्स डांगडॉग सिंगसिंग कार्बन कं., लिमि., (उत्पादक) चीन जन. गण., मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कं., लिमि., (निर्यातक) चीन जन. गण. एवं मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चीन लिमिटेड (निर्यातक), हॉग कॉर्प.

20. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार मैसर्स डांगडॉग सिंगसिंग कार्बन कं. लिमि. विचाराधीन उत्पादक है। जांच की अवधि के दौरान उसने दो असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों, यथा – मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चाईना लिमि. और मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कं. लिमि. के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। दोनों निर्यातकों ने अलग अलग उत्तर दायर किये हैं। उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को कुल *** मी. टन का निर्यात किया है। जिसमें से *** मी. टन सी आई एम एम ग्रुप कं. लिमि. के माध्यम से और *** मी. टन मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चाईना लिमि. के माध्यम से था। कमीशन, समुद्री भाड़ा, बीमा, वापस न होने वाला वैट और एस जी ए के निमित समायोजन का दावा किया गया है। उत्तर में दावा किये गये अनुसार मैसर्स जे पी ट्रेडिंग चाईना लिमि. और मैसर्स सी आई एम एम ग्रुप कंपनी लिमि., चीन जन. गण. के लिए कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

III. पाटन मार्जिन

21. प्रश्नावली के उत्तर में दिये गये व्यौरों का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा मामले की विशिष्ट स्थिति के मद्देनजर नहीं किया गया है, जिसमें घरेलू उद्योग डिफॉल्ट के रूप में मामले की समीक्षा की सहमति कर रहा है। उत्तरों में किये गये दावे के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में हैं :

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यातक	एन वी यू एस डी /मी. टन	एन ई पी यू एस डी /मी. टन	पाटनमार्जिन		
					यू एस डी /मी. टन	%	रेंज
1	लियॉग कार्बन कं. लिमि.	जिन्नई कार्बन (एच के) कं. लिमि., हॉग कॉर्प	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
2	हेफई कार्बन कं. लिमि. फंगडा कार्बन न्यू मेटेरियल कं., लिमि.	फंगडा कार्बन न्यू मेटेरियल कं., लिमि.	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
3	फूशंग ओरियंटल कार्बन कं., लिमि.	अनसीन मेटार्लुगी ग्रुप कं., लिमि.	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
4	डानडॉग जिंगजिंग कार्बन कं. लिमि.	जे पी ट्रेडिंग चीन लिमिटेड एंड सी आई एम एम ग्रुप कं., लिमि.	***	***	***	***	1-10

22. यह देखा जाता है कि उत्पादक निर्यातकों के उत्तर में दावा किया गया पाटन मार्जिन नकारात्मक है और डेंडॉग जिंगजिंग कार्बन कंपनी लिमिटेड के लिए आंशिक रूप से सकारात्मक है।

छ. क्षति का निर्धारण और क्षति की संभावना

घरेलू उद्योग के विचार

23. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये गये हैं।

आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों क्षति तथा क्षति की संभावना से संबंधित मुद्दों के संबंध में किये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :

क. संबद्ध सामानों का प्राथमिक रूप से प्रयोग इस्पात के कचरे को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह नोट करना संगत होगा कि भारत में इस्पात की मांग हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है और आगे 6 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है। इससे भारत में इस्पात उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों के लिए मांग में काफी वृद्धि हुई है तथापि, भारत में संबद्ध सामानों की आपूर्ति उसकी घरेलू मांग के अनुरूप नहीं है। जहां तक घरेलू स्रोतों से आपूर्ति का संबंध है घरेलू उद्योग पिछले कुछ वर्षों में संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का निर्यात करता रहा है और भारतीय बाजार की मांग की उपेक्षा कर रहा है।

ख. भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की मांग में भारी वृद्धि हुई है :

- i. ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की मांग वर्ष 2012 में 51128 मी. टन से बढ़कर 2017 में 1,05,066 मी. टन हो गई अर्थात लगभग 105 प्रतिशत हो गई और यह 2019 तक 1,20,971 मी. टन के स्तर तक बढ़ने की आशा है।
- ii. घरेलू उत्पादकों की क्षमता 2012 में 1,41,900 मी. टन थी और 2018 में बढ़कर 1,60,000 मी. टन हो गई जो केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- iii. घरेलू उद्योग उत्पादित ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस के 52 प्रतिशत से अधिक का निर्यात कर रहा है, इसे एच ई जी इण्डिया लिमि. द्वारा आयोजित कांफ्रेंस कॉल के विवरण में एच ई जी लिमि. द्वारा स्वीकार किया गया है और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है।
- iv. जनवरी 2012 से दिसंबर, 2012 तक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता घरेलू मांग तथा निर्यात बाजार के लिए मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी तथापि, 2012 से अब तक भारत में संबद्ध सामानों की मांग काफी बढ़ी है और इस प्रकार घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमताएं उनके द्वारा किये जा रहे निर्यातों सहित भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अब पर्याप्त नहीं है।
- v. बढ़े हुए निर्यातों से मिलाकर भारतीय मांग में काफी वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में अपर्याप्त वृद्धि से भारतीय बाजारों में संबद्ध सामानों की कमी हुई है।
- vi. घरेलू उत्पादक भारत में घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों की घरेलू मांग को पूरा करने में रुचि नहीं है परंतु इसके बजाय, घरेलू विक्रियों में निर्यात विक्री को उन्होंने प्राथमिकता दी है।
- vii. घरेलू उत्पादकों ने भारत में कम आपूर्ति की स्थिति में योगदान किया है और तदनुसार, भारत में संबद्ध सामानों की कीमतें हाल के वर्षों में काफी बढ़ी हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस के घरेलू उत्पादक पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की तुलना में भारतीय बाजार में अधिक कीमत ले रहे हैं। प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा जा सकता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की कीमतें मई 2017 में 1.5 लाख रुपए प्रति मी. टन की रेंज में थीं जो निरंतर बढ़ रही हैं और मार्च 2018 में 7-8 लाख रुपए प्रति मी. टन के स्तर पर पहुंच गई हैं। वस्तुतः ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की कीमत इस समय लगभग 10-11 लाख रुपए प्रति मी. टन है। घरेलू उत्पादकों ने चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा कीमतें वृद्धि किये जाने के बाद संबद्ध सामानों की कीमत बढ़ाई। परंतु, तब कीमतें कम नहीं कीं जब चीनी कीमतों में विशेष रूप से एच पी ग्रेड के लिए गिरावट आई। ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की लागत कीमतों के आधार पर निचले स्तर की स्टील की कुल उत्पादन लागत के लगभग 5-7 प्रतिशत की रेंज में है। संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि से इस्पात की उत्पादन लागत लगभग 1300 रुपए प्रति टन तक बढ़ गई है। अतः प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस उपलब्ध न होने से भारतीय इस्पात उद्योग कम प्रतिस्पर्धी हो गया है और उसकी वृद्धि बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
- ग. घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के आयतों से कोई क्षति नहीं हो रही है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाठनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद की अवधि में काफी सुधार हुआ है। इस समय घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। एच ई जी लिमि. और ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. दोनों की 2014-15 से आगे की वार्षिक रिपोर्टों का अवलोकन यह दर्शाता है कि राजस्व, लाभप्रदत्ता, अनियोजित पूंजी पर आय, मानदंडों के संबंध में इन कंपनियों के निष्पादन में पाठनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारी सुधार हुआ है और 2017-18 के दौरान रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। संबद्ध सामान घरेलू उद्योग के मुख्य उत्पाद हैं। घरेलू उद्योग का 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व संबद्ध सामानों से आता है।
- घ. घरेलू उद्योग के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कंपनी स्तर पर उत्पादकों का राजस्व 2014-15 में 2,78,002 लाख रुपए से बढ़कर 2017-18 में 5,84,309 लाख रुपए तक हो गया है जो लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार कंपनी स्तर पर लाभप्रदत्ता के संबंध में घरेलू उद्योग का लाभ 2014-15 में 20,154 लाख रुपए से बढ़कर 2017-18 में 2,99,353 लाख रुपए हो गया है जो लगभग 1385 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस भारी राजस्व और लाभ के महेनजर घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से किसी भी तरह 'क्षति' नहीं हो रही है।
- ड. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के लिए आर और सी ई में काफी सुधार हुआ है और वह 2014-15 में 9 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 66 प्रतिशत की ऊचाई पर है। इतने असाधारण लाभ कमाने के बाद भी घरेलू उत्पादक जुलाई 2018 – सितंबर 2018 के लिए संबद्ध सामानों की कीमत की वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक की अनौचित्यपूर्ण मांग कर

रहे हैं। इससे घरेलू इस्पात उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इस प्रकार घरेलू उद्योग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की अनिवार्य स्थिति बिलकुल नहीं बनती। इसके मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना औचित्यपूर्ण नहीं है।

च. चीन जन. गण. भारत को संबद्ध सामानों का एक प्रमुख निर्यातक देश था। तथापि, हाल के वर्षों में चीन जन. गण. सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले कई औद्योगिक संयंत्र बंद कर दिये हैं। चीन सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण 2017 के आरंभ में चीन जन. गण. में लगभग 200,000 टन प्रतिवर्ष इलेक्ट्राइस निर्माता क्षमताओं को बंद कर दिया है। इन घटनाओं का प्रभाव यह है कि चीन जन. गण. पूर्व में प्रमुख निर्यातक होने की तुलना में ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस का अब निबल आयातक हो गया है। चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन क्षमता में तीव्र गिरावट से भारत में संबद्ध सामानों की निर्यात मात्रा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों में चीन जन. गण. से आयातों के हिस्से में जनवरी 2012 में 69 प्रतिशत की अपेक्षा 2017-2018 में 55 प्रतिशत तक गिरावट आई है जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा जनवरी 2012-दिसंबर, 2012 तक 31 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 45 प्रतिशत हो गया है। इसके मद्देनजर यह अनुरोध है कि चीन जन. गण. से आयातों में गिरावट आई है और इसीलिए चीन जन. गण. के विरुद्ध लगाये गये पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने योग्य हैं।

छ. घरेलू उत्पादकों मैसर्स एच ई जी लिमि. और मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. द्वारा पत्र दायर किये गये हैं जिसमें पक्षकारों ने यह आवेदक द्वारा दायर समीक्षा आवेदन पत्र का विरोध नहीं किया है। घरेलू उत्पादकों ने कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है और सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने से दूर रहे हैं। घरेलू उत्पादकों द्वारा भाग न लेने का अर्थ है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और वे पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का पक्ष लेने में इच्छुक नहीं हैं।

ज. इस समय भारत में ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस के दो विनिर्माता अर्थात् ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. और एच ई जी हैं जिन्होंने नवंबर 2017 तक क्रमशः 98,000 मी. टन और 80,000 मी. टन का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद अत्यधिक बढ़ा है। एच ई जी की ग्रेफाइट की कुल वैश्विक क्षमता में 10 प्रतिशत क्षमता है जो उसे विश्व में पांचवा सबसे बड़ा व्यापारी बनाती है। घरेलू उद्योग का 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व संबद्ध सामानों से आता है। वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट उसे दर्शाती है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर/सूचना दायर नहीं की गई है। अतः घरेलू उद्योग के निष्पादन तथा आर्थिक मानदंडों से संबंधित अनुरोध नहीं किये गये जा सकते।

झ. चीन भारत को संबद्ध सामानों का प्रमुख निर्यातक देश था। पिछले दो वर्षों में चीन में वायु गुणवत्ता की कुछ गंभीर समस्याएं थीं। चीन सरकार ने पिछले वर्ष के आरंभ में गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं की दृष्टि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को कम करने का निर्णय लिया। इन उद्योगों के बंद होने से शेष विश्व को चीन से परिष्कृत इस्पात के निर्यात में अचानक और भारी गिरावट आई। इससे ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की कीमतों के कारण मांग और आपूर्ति में असंतुलन आया और वैश्विक क्रेता पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त नहीं कर पाये। ए एस पी ए द्वारा दायर आवेदन पत्र के अनुसार चीन जन. गण. से कुल आयातों में आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है। यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. से आयात वर्ष 2015-16 के दौरान 9871 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 1853 मी. टन हो गया। चीन जन. गण. के उत्पादकों का पाटन का इरादा नहीं है। ये आयात भारतीय बजार में मांग आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए ही किये जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

ञ. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग की हिस्से की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान काफी लाभ अर्जित किये हैं। ए एस पी ए द्वारा दायर आवेदन पत्र के अनुसार घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदत्ता में भारी सुधार हुआ है। आधार वर्ष 2014-15 के दौरान वह 20,154 लाख रुपए थी जो वर्ष 2017-18 (वार्षिक) के दौरान बढ़कर 184,249 लाख रुपए हो गई। घरेलू उद्योग के समग्र राजस्व में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। आधार वर्ष 2014-15 के दौरान वह 278,002 लाख रुपए थे जो 2017-18 (वार्षिक) के दौरान बढ़कर 438,535 लाख रुपए हो गई। उत्पादन स्तर पर भी लाभप्रदत्ता में काफी सुधार हुआ है जो 2014-15 के दौरान 139,373 लाख रुपए थी और 2017-18 (वार्षिक) के दौरान 224,196 तक बढ़ गई। एच ई जी लिमि. वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में भी निम्नलिखित उल्लेख है :

“निवल बिक्री 2016-17 में सी896.02 करोड़ से बढ़कर 2,758.40 करोड़ तक यानि 208 प्रतिशत तक बढ़ गई क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस के लिए मांग में अप्रत्याशित स्तरों तक उछाल आया। इंवी आई डी टी ए 2016-17

में सी88 करोड़ से उच्चलकर 2017-18 में सी1,734 तक हो गया। कंपनी में पूर्व वर्ष में सी50.05 की हानि के विरुद्ध 2017-18 में सी1,081.34 करोड़ का लाभ इस अवधि के लिए सूचित किया।”

इस प्रकार संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

ट. घरेलू उद्योग पूंजी पर भारी आय अर्जित कर रहा है।

ठ. विगत में कई पाटनरोधी जांचें हुई हैं जिनमें घरेलू उद्योग भारी लाभ कमा रहा था अथवा अपने उत्पाद एन आई टी से अधिक कीमत पर बेच रहा था। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन मामलों को रद्द किया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- i. चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ए.ए.ड्राइसैल वैट्रीज के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।
- ii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रो फ्लोरिक ऐसिड के आयातों से संबंधित मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा जांच।
- iii. कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनल के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच।
- iv. चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित साइट्रीक ऐसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।
- v. इण्डोनेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

ड. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग अच्छा निष्पादन कर रहा है। राजस्व, लाभ और नियोजित पूंजी पर आय (आर ओ सी ई) के संदर्भ में अर्थिक निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

ढ. मध्यावधि समीक्षा में घरेलू उद्योग का कोई विरोध नहीं है। मैसर्स एच ई जी ने अपने 5 जून, 2018 के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह समीक्षा का विरोध नहीं करना चाहेगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी मांग और आपूर्ति की स्थिति तथा चीन में घरेलू कीमतों बनाम उनकी निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए उपयुक्त दृष्टिकोण ले सकते हैं। इसी प्रकार का पत्र जी आई एल ने भी लिखा है जिसमें उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे संगत मामलों का संज्ञान लेने के बाद मामले में निर्णय लें।

ण. घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की मांग और आपूर्ति के बीच काफी अंतराल है। इस्पात के उत्पादन के लिए अपेक्षित ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की आपूर्ति 500,00 मी. टन की क्षमता बंद होने के कारण कम होती रही है, जिसमें चीन जन. गण. में 300,00 मी. टन तक की क्षमता बंद होना शामिल है। परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों की वैधिक कमी रही है।

त. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग पिछले अधिकारक प्रभावों से पूरी तरह उभर गया है और घरेलू उद्योग के सभी मानदंडों ने विगत अवधि सुधार दर्शाया है। एच ई जी की वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन निवल राजस्व, निवल लाभ, प्रचालनों से नकद, निवल मूल्य, बिक्री पर आय, नियोजित पूंजी पर आय और ऐसे ही अन्य कारकों सहित सभी वित्तीय मानदंडों के संबंध में सुधरा है। इसी प्रकार जी आई एल की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि जांच की अवधि उत्पादक के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थिति दर्शाती है। यदि पिछले 10 वर्षों से उसकी तुलना की जाये।

थ. राजस्व लाभ, निवल मूल्य पर आय, लागत सहित वित्त, कृष्ण इंक्रिटी अनुपात, नियोजित पूंजी पर आय और अन्य संगत मानदंडों सहित सभी मानदंड यह दर्शाते हैं कि उत्पादक ने जांच की अवधि 2017-18 के दौरान सबसे अधिक निष्पादन प्राप्त किया है। स्पष्ट रूप से उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है बल्कि उसमें अच्छी आय और लाभ अर्जित किये हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण की अव कोई आवश्यकता नहीं है।

द. डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि आयात 2014-15 में 14049 मी. टन के स्तर से घटकर 2015-16 में 9,871 मी. टन हो गए हैं और अंततः वर्ष 2016-17 में 2,897 मी. टन तक ही रह गये हैं। तथापि, जांच की अवधि में भारतीय बाजार में आपूर्ति की अत्यधिक कमी थी, जिससे केवल संबद्ध सामानों की कीमतें ही नहीं बढ़ी बल्कि आयातों के लिए मांग भी बढ़ गई। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि में आयात बढ़कर 11,471 मी.

टन हो गया। यह फिर भी ध्यान में रखना संगत होगा कि आयात केवल भारतीय बाजार में पूरी न की गई मांग के कारण बढ़े हैं।

ध. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2014-15 में उन आयातों के 72 प्रतिशत थे। उनका हिस्सा जांच की अवधि में घटकर 55 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार संबद्ध आयातों ने भारत में बाजार का काफी हिस्सा खोया है।

न. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है जबकि उसका उत्पादन 31 प्रतिशत तक बढ़ा। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का क्षमता उद्योग 70 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी क्षति की अवधि में लगभग 53 प्रतिशत तक बढ़ी है।

प. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने इस अवधि में वृद्धि दर्ज की है। केवल 67 प्रतिशत के स्तर से घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़कर 2016-17 में 88 प्रतिशत तक हो गया। तथापि, मांग में वृद्धि और निर्यातों पर घरेलू उद्योग के सतत जोर से जांच की अवधि में बाजार हिस्सा गिरकर 75 प्रतिशत हो गया।

फ. घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि में 16 गुणा से अधिक भारी वृद्धि हुई है। लाभ में वृद्धि से घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी वृद्धि हुई है। नकद लाभ में भी वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 10 गुणा तक की भारी वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर आय में तेजी से वृद्धि हुई है और वह जांच की अवधि में लगभग 92 प्रतिशत है। इस तथ्य से तुलना करने पर की निर्दिष्ट प्राधिकारी 22 प्रतिशत को उपयुक्त आय मानते हैं, यह सिद्ध हो जाता है कि घरेलू उद्योग को अब आयातों से संरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उपयुक्त मानी गई आय से 4 गुणा से अधिक अर्जित कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

25. प्राधिकारी ने मूल जांच के अपने 19 नवंबर, 2014 के अंतिम जांच परिणाम में यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटिट आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और इसीलिए संबद्ध देश से संबंधित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी। अब आवेदक ने दावा किया है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और घरेलू उद्योग को कोई क्षति अथवा क्षति की कोई संभावना नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति तथा क्षति की संभावना की जांच की और क्या पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 1(क) के तहत पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने अथवा बंद किये जाने की आवश्यकता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 1(क) में निम्नलिखित उल्लेख हैं:

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से उपयुक्त समयावधि समाप्त हो जाने पर अथवा अपनी निजी पहल पर जहां भी आवश्यक हो, किसी पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा पर निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी वापसी के लिए केंद्रीय सरकार सिफारिश करेंगे जहां वह इस निष्कर्ष पर आते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार बार होने की संभावना नहीं है, यदि उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है, अथवा उसमें अंतर किया जाता है इसलिए अब आवश्यक नहीं है।

26. एम टी आर जांच में घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति की संभावना की जांच करने के लिए अलग से कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(iv) के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है, नियमावली में निम्नलिखित उल्लेख हैं:

"(iv) "पाटिट आयातों से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में सभी संबंधित आर्थिक कारणों का मूल्यांकन उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतक बिक्री में कमी होने के प्राकृतिक एवं सम्भावित कारण लाभ, उत्पादन, मार्केट शेरर, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण, वास्तविक पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रबाह, वस्तुसूची इन्वेन्टीज रोजगार, वेतन, वृद्धि पूँजी निवेश में वृद्धि करने की क्षमता शामिल है।"

(vii) "वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिन में पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

(क) भारत में पाठित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्यास वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्यास मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्यास वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाठित निर्यातों में पर्यास वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।"

अ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

27. नियमावली के अनुबंध-॥। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निधारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और लाभ, नियोजित पूँजी पर आय आदि सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का वस्तुपरक एवं निषेक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। प्राथिकारी के पास उपलब्ध घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित आंकड़े यह दर्शते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

i. लाभप्रदत्ता और नियोजित पूँजी पर आय

28. आवेदक के अनुसार क्षति जांच की अवधि में और विशेष रूप से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कर पूर्व लाभ व्याज और कर पूर्व लाभ संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
1	पी बी टी	रु. लाख	20,154	11,771	7,058	2,99,353
2	व्याज	रु. लाख	7,666	5,304	5,919	6,286
3	पी बी आई टी	रु. लाख	27,819	17,075	12,977	3,05,639
4	कुल पूँजी	रु. लाख	4,62,044	4,21,423	4,15,470	6,13,153
5	वर्तमानदेवताएं	रु. लाख	1,44,849	1,18,079	1,14,405	1,50,149
6	नियोजित पूँजी	रु. लाख	3,17,194	3,03,344	3,01,065	4,63,004
7	आर ओ सी ई	%	9	6	4	66
7a	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	49	753

स्रोत: घरेलू उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट

29. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का कर पूर्व लाभ, व्याज और कर पूर्व लाभ पूर्व वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ा है। व्याज ने क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान थोड़ी घटती प्रवृत्ति दर्शायी है। घरेलू उद्योग की कुल परिसंपत्तियां भी पूर्व वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग की नियोजित पूँजी पर आय में काफी सुधार हुआ है और आधार वर्ष में 9 प्रतिशत से तुलना करने पर जांच की अवधि में वह 66 प्रतिशत की ऊँचाई पर है।

ii. मांग—आपूर्ति अंतराल

30. आवेदक के अनुसार संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की नियात विक्री से संबंधित सूचना निम्नलिखित है।

तालिका: घरेलू उद्योग की नियात विक्री

क्र. सं.	सी टी एच	इकाई	जन. 2012- दिसं. 2012	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
1	85451100	मी. टन		69,044	52,778	62,576	82,746
2	85451900	मी. टन		1,836	1213	545	1,113

3		कुल	74,844	70,880	53,991	63,121	83,589
4		सूची		100	76	89	118

स्रोत: निर्यात आयात आंकड़ा बैंक वाणिज्य मंत्रालय

31. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में काफी वृद्धि हुई है और संबद्ध सामानों की घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री में भी निरंतर वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। बढ़े हुए आयातों से मिलाकर भारतीय मांग में काफी वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं में अपर्याप्त वृद्धि से भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की कमी हुई है।

तालिका: घरेलू उद्योग की क्षमता

क्र. सं.	कम्पनी	इकाई	जन. 2012- दिसं. 2012	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई
1	ग्राफिटे इण्डिया लिमि.	मी. टन		80,000	80,000	80,000	80,000
2	एच ई जी लिमि.	मी. टन		80,000	80,000	80,000	80,000
3	कुल		1,41,900	160,000	160,000	160,000	160,000

स्रोत: एच ई जी लिमि. की वार्षिक रिपोर्टें ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. की सरकारी वेबसाइट और 19 नवंबर, 2014 के मूल अंतिम जांच परिणाम।

32. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 1,60,000 मी. टन की संस्थापित क्षमता है और वह भारतीय बाजार में भारी मांग के बावजूद अपनी क्षमता का लगभग 52 प्रतिशत का निर्यात कर रहा है। घरेलू उत्पादकों के लिए क्षमता 2012 में अर्थात मूल जांच की जांचावधि में 1,41,900 मी. टन थी और वर्तमान जांचावधि में वह बढ़कर 1,60,000 मी. टन हो गई जो 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार के लिए मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त थी तथापि, मूल जांच की जांचावधि से वर्तमान एम टी आर जांच की जांचावधि के बीच भारत में संबद्ध सामानों की मांग में काफी वृद्धि हुई है और इस प्रकार घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमताएं भारतीय मांग को पूरा करने तथा उनके द्वारा किये जा रहे निर्यातों के लिए अब पर्याप्त नहीं हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस की मांग 2012 में 51,128 मी. टन से बढ़कर 2017 में 1,05,066 मी. टन हो गई। अर्थात लगभग 105 प्रतिशत हो गई और 2019 तक इसके 1,20,971 मी. टन के स्तर तक बढ़ने की आशा है।

iii. आयात मात्रा और हिस्सा

33. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी ने इस पर विचार किया कि क्या संबद्ध देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई है। अतः प्राधिकारी ने अनुबंध II (vii) (ख) के अनुसार संबद्ध देश के आयातों और क्षमताओं में वृद्धि की संभावना की जांच की है, जिसमें यह उल्लेख है कि भारतीय निर्यात में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पार्टिट निर्यातों की संभावना दर्शने वाले निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि, पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य अथवा आसान। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण लगभग 200,000 से 3,00,000 मी. टन प्रतिवर्ष की इलेक्ट्राइस निर्माता क्षमताओं के औद्योगिक संयंत्र बंद कर दिये हैं। इन घटनाओं का प्रभाव यह है कि चीन जन. गण. अब पूर्व में प्रमुख निर्यातक होने के विरुद्ध ग्रेफाइट इलेक्ट्राइस का शुद्ध आयातक हो गया है, जिससे भारत को संबद्ध सामानों की निर्यात मात्रा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। परिणामस्वरूप, आयात हिस्से में गिरावट आई। अतः संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	जन. 2012- दिसं. 2012	2015-16	2016-17	पी ओ आई
1	आयात					
1क	चीन जन. गण	मी. टन	13,600	9,871	2,897	11,471
1ख	चीन के अलावा अन्य देश	मी. टन	6,240	7,348	4,073	9,460

1ग	कुल आयत	मी. टन	19,840	17,219	6,970	20,931
2	आयात में बाजार हिस्सा					
2क	चीन जन. गण.	%	69	57	42	55
2ख	अन्य देश	%	31	43	58	45

स्रोतः एचस्लोतस्रोतः, ई जी लिमि. की वार्षिक रिपोर्ट ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. की सरकारी वेबसाइट और 19 नवंबर, 2014 के मूल अंतिम जांच परिणाम।

34. यह देखा जाता है कि भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयत में चीन जन. गण. आयातों का हिस्सा 2012 में 69 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 55 प्रतिशत हो गया जबकि अन्य देशों से आयात का हिस्सा 2012 में 31 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 45 प्रतिशत तक हो गया।

iv. भारत में संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि

35. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों की जांच की है और नोट किया कि भारत में संबद्ध सामानों की कीमतें जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी हैं।

ज. क्षति विश्लेषण

36. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और कोई आंकड़े/ सूचना प्रस्तुत नहीं की है, न ही एम टी आर जांच का विरोध कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी क्षति रहित कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं थी।

ज. क्षति तथा क्षति की संभावना के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच किये गये विभिन्न मुद्दों का सार

37. प्राधिकारीनोट करते हैं कि :

- मूल जांच में घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादकों अर्थात मैसर्स एच ई जी लिमि. और ग्रेफाइट इण्डिया लिमि. द्वारा कोई विरोध नहीं।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता और नियोजित पूँजी पर आय जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी है।
- घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं का इष्टतम रूप उपयोग किया गया है।
- मांग और आपूर्ति में भारी अंतराल के फलस्वरूप भारत में संबद्ध सामानों की कीमतों में वृद्धि हुई।
- 2,00,000 मी. टन से 3,00,000 मी. टन क्षमता के संयंत्र बंद करने के कारण चीन से निर्यातोन्मुखता में कमी।
- संबद्ध देश से आयात मात्रा और हिस्से में गिरावट।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

38. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए मुद्दे जांच के दौरान पहले ही उठा दिए गए हैं और संगत पैराओं में उनका समाधान भी कर दिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की जा रही है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

40. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- घरेलू उद्योग ने शुल्क की प्रस्तावित राशि का विरोध नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें पाटनरोधी शुल्क द्वारा दिए गए संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब घरेलू उद्योग को अब शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको जारी रखने का अर्थ केवल आयातों और संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत भार ही है।

- ii. यदि लागू शुल्क रद्द किया जाता है तो कोई संभावना नहीं है कि संबद्ध देशों से आयात बढ़ेंगे जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- iii. यद्यपि, भारत में संबद्ध सामानों की मांग लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है, तथापि, घरेलू उद्योग ने मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। संबद्ध सामानों के लिए मांग कई गुना बढ़ने की आशा है क्योंकि इसपात की मांग में वृद्धि हो रही है, तथापि, घरेलू उद्योग निर्यातों पर जोर दे रहा है, वह भारतीय स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों की वैश्विक कमी है। संबद्ध सामानों की आपूर्ति इस कारण से भी और कठिनाई में होने की संभावना है कि संबद्ध सामानों के लिए कम्बी सामग्री, निडिल कोक, आपूर्ति में कम है। वस्तुतः दोनों घरेलू उत्पादकों ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में इसे स्वीकार किया है।
- iv. आयातों की मात्रा क्षति की अवधि में काफी कम हुई है, जांच की अवधि में आयात बढ़ने का कारण यह है कि घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में अक्षम था क्योंकि उनका मुख्य जोर निर्यातों पर रहा है।
- v. संबद्ध आयात उत्पादन और खपत के संबंध में भी कम हुए हैं। आयातों का बाजार हिस्सा इस अवधि में 23 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया।
- vi. घरेलू उद्योग का निष्पादन सभी मानदंडों में काफी सुधरा है। उत्पादन एवं क्षमता उपयोग के अनुमानित आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वे क्षति की अवधि में बढ़े हैं। केवल घरेलू विक्री ही नहीं बढ़ी है बल्कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी बढ़ा है।
- vii. घरेलू उद्योग लगभग उसकी लागत के बराबर प्रति यूनिट लाभ अर्जित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्पष्ट रूप से विक्री कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि से काफी अधिक है। इस प्रकार, सामानों की कीमतों का न तो न्यूनीकरण हो रहा है और न ही हास। लाभ में काफी वृद्धि से घरेलू उद्योग के अनुमानित नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय, दोनों में कम से कम 10 गुना तक वृद्धि हुई है।
- viii. मालसूची धारण अवधि 2014-15 में 31 दिन से काफी घटकर जांच की अवधि में 10 दिन से भी कम हो गई है।
- ix. ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में काफी सुधार दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति के ऋण अनुपात में भी सुधार हुआ है जो 2014-15 में 42 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में केवल 28 प्रतिशत तक रह गया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. यह नोट किया जाता है कि प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों की जांच उपर्युक्त संगत पैराओं में प्राधिकारी द्वारा पहले ही कर दी गई है।

ट. निष्कर्ष

42. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:

- i. भारत में कुल आयातों में चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयात 2012 में 69 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 55 प्रतिशत हो गए, जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा 2012 में 31 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 45 प्रतिशत हो गया।
- ii. घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है तथा संबद्ध देश से तथाकथित पारित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।
- iii. भारत में संबद्ध सामानों की अत्यधिक कमी है और बढ़े हुए निर्यातों को मिलाकर भारतीय मांग में काफी वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं में काफी वृद्धि से भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की भारी कमी हो गई है।
- iv. प्राधिकारी के समक्ष मामले के तथ्य पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं दर्शाती।

ठ. सिफारिश

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच शुरू करने पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संपर्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच करने पर यह सिद्ध होता है कि यदि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा वार-वार रहने की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी का यह मत है कि वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक नहीं है। इसके मद्देनजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 13.02.2015 की अधिसूचना संख्या 4/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचित, चीन जन. गण. के मूल के अथवा

वहां से निर्यातित "ग्रेफाइट इलैक्ट्रोइस ऑफ आल डायमीटर्स" के संबंध में पाटनरोधी शुल्क बंद करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

44. इस जांच परिणाम के कारण केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महा निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

(Final Findings)

Sub: Final Finding in Mid-term Review (MTR) investigation with regard to the antidumping duties in force on the imports of Graphite Electrodes of all diameters originating in or exported from China PR.

F. No. 7/13/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or "AD Rules") thereof. An application for Mid-Term Review ("MTR") investigation was filed by Alloy Steel Producers Association of India ("ASPA") (hereinafter referred to as "the applicant"), before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority").

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Whereas, the Authority had initiated the original investigation vide 14/02/2013-DGAD dated 20.5.2013 on a petition filed by M/s HEG Ltd and M/s Graphite India Ltd. The Final Findings were notified vide Notification No. 14/02/2013-DGAD dated 19.11.2014 recommending imposition of definitive anti-dumping duty on imports of "Graphite Electrodes of all diameters" (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 4/2015-Customs (ADD) dated 13.2.2015.

3. Whereas, Alloy Steel Producers Association of India, on behalf of importers, have submitted an application requesting for initiation of a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. It has been claimed by the applicant that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer warranted.

B. INITIATION

4. Whereas, Rule 23 (1A) of the AD Rules read with Section 9A of the Act require that the designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti - dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

5. Having regard to the information provided by the applicant substantiating the need for such review and indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority, vide Notification No. 7/13/2018-DGAD dated 4th April, 2018, initiated the Mid-term Review (MTR) investigation with regard to the final findings notified vide Notification No. 14/02/2013-DGAD dated 19th November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No. 4/2015-Customs dated 13th February, 2015, to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties.

C. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed by the Authority with regard to the present investigation:

- i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 4th April, 2018 to the Embassy of China PR in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per the available information. All parties were requested to provide their views and data within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to Embassy of China PR in India along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
- ii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the MTR to the following known producers/exporters in China PR and sent the exporter's questionnaires to elicit relevant information within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. M/s Fushun Carbon Co., Ltd.,
 - b. M/s Jilin Carbon Imp. & Exp. Company,
 - c. M/s Kaifeng Carbon Co., Ltd.
 - d. M/s Fangda Carbon New Material Co., Ltd.,
 - e. M/s Sinosteel Zhejiang Co., Ltd.,
 - f. M/s Sinosteel Jilin Carbon Co. Ltd.,
 - g. M/s Linyi County Lubei Carbon Co., Ltd.,
 - h. M/s Shandong Basan Carbon Plant,
 - i. M/s Anseen Metallurgy Group Co., Ltd.,
 - j. M/s Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd,
 - k. M/s Sichuan Guanghan Sida Carbon Co. Ltd.,
 - l. M/s Fushan Oriental Carbon Co. Ltd.,
 - m. M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd.,
 - n. M/s Linghai Hongfeng Carbon Products Co Ltd.,
 - o. M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd.,
 - p. M/s CIMM Group Co. Ltd.,
 - q. M/s CIMM Donghai Advanced Carbon Co., Ltd.,
- iii. On the request of certain interested parties, the Authority extended the time period for submission of Questionnaire responses by the interested parties up to 15.06.2018.
- iv. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from China PR have responded by filing exporters questionnaire response:
 - a. M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd (Producer) M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd, HongKong (Exporter),
 - b. M/s Hefei Carbon Co., Ltd, China PR (Producer) and M/s. Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China PR (Exporter and producer),
 - c. M/s Fushun Oriental Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR and M/s Ansen Metallurgy Group Co., Ltd., (Exporter) China PR,
 - d. M/s Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR, M/s CIMM Group Co., Ltd., (Exporter) China PR and M/s JP Trading China Limited, (Exporter), Hong Kong,
- v. The Enterprises Rights Protection Centre of CCPIT/CCOIC has filed written submissions only.
- vi. Letters were also sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. SAIL, Alloy Steel Plant
 - b. SAIL, Bhilai Steel Plant
 - c. SAIL, Bokaro Steel Plant
 - d. SAIL, Rourkela Steel Plant

- e. SAIL, Durgapur Steel Plant
- f. SAIL, Visvesvaraya Iron & Steel Plant
- g. Bhushan Steel Ltd.
- h. Sunflag Iron & Steel Co. Ltd.
- i. Jindal Steel & Power Ltd.
- j. Jindal Stainless Ltd.
- k. Lloyd Steel Inds. Ltd.
- l. Mukand Ltd.
- m. JSW Ispat Steel
- n. ISMT Limited.
- o. Bhushan Power & Steel Limited.

vii. In response to the above notification, the following users/importers have filed users/importers questionnaire response:

- a. SAARLOHA Advance Materials Private Limited
- b. RMG Alloy Steel Ltd.
- c. Vardhman Special Steels Ltd.
- d. JSW Steel Ltd.

viii. Letters were sent to M/s Graphite India Ltd. and M/s HEG Ltd., the known domestic producers of the subject goods in India constituting the domestic industry in the original investigation, for necessary information and response. M/s. Graphite India Ltd. and M/s HEG Ltd. did not file any response, injury related data or comments in the subject investigations. M/s HEG Ltd vide letter dated 5.6.2018 submitted that they have not opposed the review and Directorate can take a suitable view considering the demand/supply position and domestic prices in China vs. their export prices. M/s Graphite India Ltd. vide letter dated 9.6.2018, submitted that the case may be decided suitably after taking cognizance of the contemporary pricing of Chinese products in India and China and other relevant/ related matters.

ix. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 (POI). However, injury examination was to be conducted for the period April 2014-March 2015, April 2015-March 2016, April 2016-March 2017 and the POI.

x. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 17th July, 2018. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have also been considered by the Authority, wherever found relevant, in this Final Finding.

xi. Information provided by interested parties on confidential basis has been examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis have been directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xiii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Finding on the basis of the facts available.

xiv. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present

investigation, have been appropriately considered by the Authority.

- xv. A Disclosure Statement was issued on 1.8.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 7.8.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately
- xvi. ‘***’ In Final Finding, represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 7. The product under consideration in the present mid-term review investigation, is ‘Graphite Electrodes of all diameter’, originating in or exported from China PR. The product scope is the same as defined in the original investigation.
- 8. The main function of Graphite Electrodes is to be used for melting of steel by passing electric current into the charge fed into the furnaces. This method of steel making is also known as secondary steel making. Graphite Electrodes are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Graphite electrodes can be broadly categorized as Ultra High Power (UHP) and others which include the High Power Grade (HPG) and Normal Power Grade (NPG). Accordingly, they are required to have properties capable for taking such high current and power feeds.
- 9. The product under consideration is classified under Customs Tariff Heading 8545 and are primarily imported under tariff item number 85451100 and 85451900 of the Custom Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- 10. The applicant has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being imported into India. The two have comparable characteristics in terms of parameters such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. They are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules.
- 11. Since none of the interested parties other than the applicant have made any submission with regard to product under consideration and like article, the scope of the product under consideration and like article in the present review remains the same as that in the original investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 12. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules defines domestic industry as under:
2(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”;
- 13. During the original investigation, M/s Graphite India Ltd. and M/s HEG Ltd. constituted the domestic industry. The position remains unaltered during the POI of the present investigation and no submission has been made by any interested party to the contrary. In view of the said position, the Authority notes that M/s Graphite India Ltd. and M/s HEG Ltd. constitute domestic industry in the present MTR investigation within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti- dumping Rules.

F. DUMPING MARGIN AND INJURY MARGIN

- 14. The application has been filed by the Association on behalf of member importers claiming that there is no injury and no likelihood of injury to Domestic Industry as the economic performance of the domestic industry in terms of revenue, profits and return on capital employed (ROCE) has improved significantly. The Domestic Industry has been exporting significant volumes of the subject goods in the last few years and is neglecting the demands of the Indian market resulting into scarcity of the subject goods in India. Domestic producers in India has neither challenged the contentions raised by the applicant or submitted any costing data.
- 15. The following groups of producers and exporters of the subject goods originating in or exported from China PR have filed questionnaire response to this mid-term review:
 - a. M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd (Producer) M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd, HongKong (Exporter).

- b. M/s Hefei Carbon Co., Ltd, China PR (Producer) and M/s. Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China PR (Exporter and producer)
- c. M/s Fushun Oriental Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR and M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., (Exporter) China PR
- d. M/s Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR, M/s CMM Group Co., Ltd., (Exporter) China PR and M/s JP Trading China Limited, (Exporter), Hong Kong.

I. NORMAL VALUE

16. It is noted that the Indian producers namely M/s. Graphite India Ltd. and M/s HEG Ltd. who were the Domestic Industry in the original investigation did not file any response, injury related data or comments in the subject investigations neither opposed the investigation. However, exporters from the subject countries have filed questionnaire responses in which they have claimed the normal value and the net export price. None of the producer exporter have claimed market economy status. The information submitted in the responses has not been verified, however, the dumping margins on the basis of normal value and net export price as claimed by the producer exporters in their responses are detailed in the Dumping Margin table below:

II. EXPORT PRICE

a. M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd (Producer) M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd, HongKong (Exporter)

17. As per the Exporters Questionnaire response M/s Liaoyang Carbon Co. Ltd is the producer of PUC and have exported to India only through their unrelated trading company M/s Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd, HongKong. They have exported *** MT to India during the POI. Adjustment towards Inland Transportation (upto FOB), Ocean Freight, Insurance and Port & Other related expenses have been claimed. The export price for exports to India at ex-factory level, as claimed in the response, is shown in the Dumping Margin Table below

b. M/s Hefei Carbon Co., Ltd, China PR (Producer) and M/s. Fangda Carbon New Material Co. Ltd, China PR (Exporter and producer)

18. As per the Exporters Questionnaire response M/s Fangda Carbon New Material Co., Ltd., China PR ("Fangda Carbon") is a producer of Graphite Electrodes of various grades viz. RP, HP, HD, SHP, UHP grades. The company has reported *** MT export to India in the period of investigation. Out of these exports, the company exported *** MT of Graphite Electrodes which are manufactured by them and the balance *** MT was manufactured by M/s Hefei Carbon Co., Ltd. The sales to India were carried out on CIF basis. Adjustment towards inland freight, handling charges, ocean freight have been claimed. The export price for exports to India at ex-factory level, as claimed in the response, is shown in the Dumping Margin Table below.

c. M/s Fushun Oriental Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR and M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., (Exporter) China PR

19. As per the Exporters Questionnaire response, M/s Fushun Oriental Carbon Co., Ltd is the producer of PUC. During the POI, its products are exported through M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd which is only a trading company. M/s Anssen Metallurgy Group Co., Ltd., has filed response separately. They have exported *** MT to India during the POI. Adjustment towards Ocean Freight, Insurance, Inland transportation, Port and other related expenses, Credit Cost and VAT have been claimed. The export price at ex-factory level, as claimed in the response, is shown in the Dumping Margin Table below.

d. M/s Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd., (Producer), China PR, M/s CMM Group Co., Ltd., (Exporter) China PR and M/s JP Trading China Limited, (Exporter), Hong Kong,

20. As per the Exporters Questionnaire response M/s Dandong Xinxing Carbon Co.,Ltd. is the producer of PUC. During the POI it had exported the subject goods to India through 2 unrelated trading companies namely M/s JP Trading China Limited & M/s CMM Group Co., Ltd. Both the exporters have filed responses separately. They have exported a total of *** MT to India during the POI, out of which *** MT was through CMM Group Co. Ltd and *** MT through M/s J P Trading China Ltd. Adjustment towards Commission, ocean Freight, Insurance, Non-Refundable Vat and SGA have been claimed. The export price for M/s JP Trading China Limited & M/s CMM Group Co., Ltd, China PR at ex-factory level, as claimed in the response, is shown in the Dumping Margin Table below:

III. DUMPING MARGIN

21. The details claimed in the questionnaire responses have not been verified by the Authority in view of the typical situation of the case wherein DI is by default agreeing for review of the case. The normal value, export price and

dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject country, as claimed in the responses is as below:

SN	Producer	Exporter	NV USD/MT	NEP USD/MT	Dumping Margin		
					USD/MT	%	Range
1	Liaoyang Carbon Co. Ltd	Jinnai Carbon (HK) Co. Ltd, HongKong	***	***	(***)	(***)	Negative
2	Hefei Carbon Co., Ltd. Fangda Carbon New Material Co., Ltd	Fangda Carbon New Material Co., Ltd	***	***	(***)	(***)	Negative
3	Fushun Oriental Carbon Co., Ltd	Anssen Metallurgy Group Co., Ltd	***	***	(***)	(***)	Negative
4	Dandong Xinxing Carbon Co.,Ltd	JP Trading China Limited and CIMM Group Co., Ltd	***	***	***	***	1-10

22. It is seen that the dumping margin claimed in the responses of the producer exporters is negative and marginally positive for exports of Dandong Xinxing Carbon Co. Ltd.

G. DETERMINATION OF INJURY AND LIKELIHOOD OF INJURY

Views of the Domestic Industry

23. No submissions have been made by the Domestic Industry in the present investigation.

Views of the Applicant and other interested parties

24. The following are the submissions with regard to injury and likelihood of injury related issues made by the Applicant and other interested parties considered relevant by the Authority.

- The subject goods are primarily used for melting of steel scrap. It would be relevant to note that the demand of steel in India has significantly increased in the recent years and is expected to further increase at a rate of 6%. This has led to a substantial increase in the demand for the subject goods by the steel industry in India. However, the current supply of the subject goods in India is not in line with its domestic demand. As far as supply from domestic sources is concerned, the Domestic Industry has been exporting significant volumes of the subject goods in the last few years and is neglecting the demands of the Indian market.
- The demand for the subject goods in the Indian market has shown huge increase:
 - Demand for Graphite electrodes has increased from 51,128 MT in 2012 to 1,05,066 MT in 2017 i.e., approximately 105% and it is further expected to rise to a level of 1,20,971 MT by 2019;
 - Capacity for domestic producers was 1,41,900 MT in 2012 and increased to 1,60,000 MT in 2018 representing only a 12% increase;
 - Domestic Industry is exporting more than 52% of the graphite electrodes produced. This has been admitted by HEG Ltd. in the transcripts of the conference call held by HEG India Ltd and available in the public domain;
 - The production capacity of domestic producers in January 2012 to December 2012 was sufficient to meet the demand in domestic market as well as for export market. However, between 2012 to present, the demand for the subject goods in India has increased significantly and thus, the production capacities of domestic producers are no longer sufficient to meet the Indian demand along with exports being undertaken by them;
 - An insignificant increase in production capacities of the domestic producers compared to the significant rise in Indian demand combined with increased exports has led to shortage of subject goods in the Indian market;
 - The domestic producers are not able to cater to the domestic demand in India. Moreover, the domestic producers are not interested in catering to the domestic demand but have, rather,

prioritized export sales over domestic sales;

vii. The Domestic producers have contributed to the situation of short-supply in India and accordingly, the prices of the subject goods in India have increased substantially in recent years. Domestic producers of graphite electrodes are already charging higher price in Indian market as compared to price in international market. On the basis of analysis of the User's Questionnaire Responses, it can be observed that the prices of graphite electrodes were in the range of Rs. 1.5 Lacs per MT in May 2017 which has been consistently rising and reached a level of Rs. 7-8 Lacs per MT in March 2018. In fact, Graphite Electrodes are presently priced around Rs. 10-11 Lacs per MT. Domestic producers raised the price of subject goods following the rise in price by producers from China PR but have not reduced the prices when Chinese prices have declined, particularly for HP Grade. Cost of graphite electrodes is approximately in range of 5-7% of total cost of production of downstream steel depending upon the prices. The increase in price of subject goods has increased the cost of production of steel by approximately Rs.1300 per ton. Hence, non-availability of Graphite Electrodes at competitive prices is making Indian steel industry less competitive and severely impacting their growth, as well.

c. The domestic producers are not suffering any injury from the imports of the subject goods. The performance of the domestic industry has shown significant improvement in the period after the imposition of anti-dumping duty. Domestic Industry is not facing any injury at present. A perusal of the Annual Reports from 2014-15 onwards of both HEG Ltd. and Graphite India Ltd, shows that performance of these companies with regard to revenue, profitability and return on capital employed parameters improved tremendously since the imposition of anti-dumping duties and has reached record levels during 2017-18. The subject goods are the main product of the Domestic Industry. More than 90% of revenue of Domestic Industry comes from the subject goods.

d. The data of the Domestic Industry shows that the revenue of the producers at company level has increased from Rs. 2,78,002 lakhs in 2014-15 to Rs. 5,84,309 lakhs in 2017-18 representing a nearly 110% increase. Similarly, with regard to profitability, the profits of Domestic Industry at company level have increased from Rs. 20,154 lakhs in 2014-15 to Rs 2,99,353 lakhs in 2017-18 representing a nearly 1385% increase. In view of such tremendous revenue and profits, the domestic industry is clearly not "injured" in any sense.

e. Further, ROCE for the domestic industry has significantly improved and is as high as 66% in 2017-18 when compared to 9% in 2014-15. Even after making such abnormal profits, domestic producers are unjustifiably asking for a price hike of subject goods of more than 10% for July 2018-September 2018. This will adversely affect competitiveness of domestic steel producers. Thus, the domestic industry has seen a remarkable improvement and the situation mandating the imposition of anti-dumping duties no longer exists. In view thereof, the continued imposition of anti-dumping duties is not justifiable.

f. China PR was one of the major exporting countries of the subject goods to India. However, in the recent years, the Government of China PR has shut down many industrial plants producing the subject goods on account of environmental concerns. The Chinese government has shut down nearly 200,000 tonnes per annum of electrode making capacities in China PR in the beginning of 2017 due to environmental concerns. The effect of these developments is that is that China PR has now become a net importer of Graphite Electrodes as against being a major exporter earlier. A sharp reduction in production capacity for the subject goods in China PR has seriously impacted the export volumes of the subject goods to India.

g. The share of imports from China PR in total imports of the subject goods into India has declined from 69% in January 2012 to December 2012 to 55% in 2017-18 whereas the share of imports from other countries has increased from 31% in Jan 2012-Dec 2012 to 45% in 2017-18. In view thereof, it is submitted that the imports from China PR have declined and therefore, the anti-dumping duties imposed against China PR merit revocation.

h. Two letters have been filed by the domestic producers, M/s. HEG Ltd. and M/s. Graphite India Ltd. wherein the parties have not opposed the review application filed by the Applicant herein. The domestic producers have not appointed any representative and refrained from attending the public hearing. The non-participation by the domestic producers implies that the domestic industry is not suffering any injury anymore and is not interested in defending the continuation of anti-dumping duties

i. Presently there are two manufacturers of graphite electrodes in India namely Graphite India Limited

and HEG which reportedly produced 98,000 MT and 80,000 MT of the product respectively, till November 2017. The performance of the DI has improved remarkably after the imposition of Anti-Dumping Duty. HEG has 10% of the total global capacity of Graphite, making it fifth largest player in the world. More than 90% of the revenue of the DI comes from the subject goods. The annual reports for the year 2016 – 17 depict the same. No questionnaire response/information has been filed by DI, therefore submissions on the performance and economic parameters of the DI cannot be made.

- j. China was the major exporting country of the subject goods to India. In the past two years, China had some serious problems with air quality. The Chinese government early last year decided to reduce some of the highly polluting Industries emanating from serious environmental concerns. These closures have led to a sudden and significant drop of export of finished steel from China to the rest of the world. All this led to a demand-supply imbalance with Graphite Electrode prices soaring and global buyers scrambling to secure adequate supplies. As per the application filed by ASPA, total imports from China PR have declined substantially during the period of investigation as compared to the base year 2015-16. It can be seen that imports from China PR has declined from 9871 MT during the year 2015-16 to 1853 MT during the POI. The producers from China PR do not have the intention of dumping. Such imports are being done only to fill the demand supply gap in the Indian market. This shows that there is no volume effect caused by imports during the period of investigation.
- k. After imposition of anti-dumping duty, the share price of Domestic Industry has increased tremendously. The Domestic Industry has earned substantial profits during the period of investigation. As per the Application filed by ASPA, the overall profitability of the Domestic Industry has improved substantially. During the base year 2014-15, it was Rs. 20,154 lacs which increased to Rs. 184,249 lacs during the year 2017-18 (Annualised). The overall revenue of the Domestic Industry has also increased substantially. During the base year 2014-15, it was Rs. 278,002 lacs which increased to Rs. 438,535 lacs during the year 2017-18 (Annualised). At product level also, the profitability has improved significantly, from Rs. 139,373 lacs during 2014-15 to 224,196 during 2017-18 (Annualised). The annual report for the year 2017-18 of HEG limited also state that:

“Net sales increased by 208% from C896.02 crore in 2016-17 to C2,758.40 crore as the demand for graphite electrodes surged to unprecedented levels. EBIDTA jumped from C88 crore in 2016-17 to C1,734 crore in 2017-18. The Company reported a Profit for the period at C1,081.34 crore in 2017- 18 against a C50.05 crore loss in the previous year.”

Thus, imports from subject countries are not causing any injury to the Domestic Industry.

- l. The Domestic Industry is earning tremendous return on capital.
- m. In past, there are various anti-dumping investigations wherein the Domestic Industry was earning huge profits or selling its products at price above NIP hence the Designated Authority has terminated those cases. Few examples are as follows:
 - i. Anti-Dumping Investigation concerning imports of *AA Dry Cell Batteries* originating in or exported from China PR and Vietnam;
 - ii. Mid-term anti-dumping review investigation concerning imports of *Hydrofluoric Acid* originating in or exported from China PR;
 - iii. Mid-term review investigation concerning imports of *Phenol* originating in or exported from Korea RP;
 - iv. Anti-dumping investigation concerning imports of *Citric Acid* originating in or exported from China PR, Korea RP and Ukraine;
 - v. Anti-dumping investigation concerning imports of *Gypsum Plaster Board* originating in or exported from Indonesia and Thailand.
- n. It can be concluded that the Domestic Industry is performing well. The economic performance in terms of revenue, profits and return on capital employed (ROCE) has improved significantly.
- o. There is no opposition of domestic industry to the mid-term review. M/s HEG in their letter dated 5th June, 2018 have clearly stated that it would not like to oppose the review and the Designated Authority may take a suitable view considering the demand-supply position and the domestic prices in China versus their export prices. Similar letter has been written by GIL, wherein they have requested the Authority to decide the case after taking cognizance of the relevant matters.
- p. There is a significant gap between demand and supply of the subject goods in the domestic market. The

supply of graphite electrodes required for production of steel has been on a decline, owing to capacity of 500,000 MT being shut down, which includes shut down of capacity to the tune of 300,000 MT in China PR itself. Resultantly, there has been a global shortage of the subject goods.

- q. It is submitted that the domestic industry has fully recovered from the injurious effects of past dumping, and all parameters of the domestic industry have shown improvement over the past period. From the annual report of HEG, it is clearly showing that the performance of the producer has improved with regard to all financial parameters, including net revenue, net profits, cash from operations, net worth, return on sales, return on capital employed and such other factors. Similarly, the annual report of GIL shows that the period of investigation shows the most favourable position for the producer, when compared over the last 10 years. All parameters including revenue, profits, return on net worth, finance cost cover, debt equity ratio, return on capital employed and other relevant parameters demonstrate that the producer has achieved the highest ever performance during the period of investigation, 2017 – 18. Clearly, the industry is no longer suffering, but has earned phenomenal revenues and profits. Therefore, it no longer needs protection of anti-dumping duties.
- r. From the DGCI&S import data, it can be seen that the imports declined from the level of 14,049 MT in 2014 – 15 to 9,871 MT in 2015 – 16 and finally to merely 2,897 MT in the year 2016 – 17. However, in the POI there was an extreme shortage of supply in the Indian market, which not only increased the prices of the subject goods, but also increased the demand for imports. Resultantly, the imports increased to 11, 471 MT in the period of investigation. It is nevertheless relevant to bear in mind that the imports have increased only due to the unfulfilled demand in the Indian market.
- s. The imports from the subject country accounted for a 72% of the total imports in the year 2014 – 15, their share has reduced to 55% in the period of investigation. Thus, the subject imports have lost a significant share of the market in India.
- t. The capacity of the domestic industry has remained constant, while its production has increased by 31%. Resultantly, the capacity utilisation of the domestic industry has gone up from 70% to more than 91%. Further, the domestic sales of the domestic industry have also increased, by around 53% over the injury period.
- u. The market share of the domestic industry has recorded an increase over the period. From a level of merely 67%, the market share of the domestic industry grew to 88% in 2016 – 17. However, with the increase in demand and continued focus of domestic industry on exports, the market share dipped to 75% in the period of investigation.
- v. The profits of the domestic industry have shown a drastic increase over the period, of more than 16 times as compared to the year 2014 – 15. With the increase in profits, the cash profits of the domestic industry have also increased. The cash profits have recorded a sharp increase by nearly 10 times in the period of investigation, as compared to the year 2014 – 15. Likewise, the return on investment earned by the domestic industry has increased sharply and is nearly 92% in the period of investigation. When compared with the fact that the Designated Authority considers 22% to be a reasonable return, it becomes evident that the domestic industry no longer requires protection from the imports, as it is earning more than 4 times the return considered reasonable.

Examination by the Authority

25. The Authority in its final findings dated 19th November, 2014 of the original investigation had concluded that the domestic industry was suffering material injury due to the dumped imports from the subject country and therefore recommended for imposition of Anti-Dumping Duty on the subject goods from the subject country. Now, the applicant has claimed that the circumstances have changed and there is no injury and no likelihood of injury to the Domestic Industry. Accordingly, the Authority examined the injury and likelihood of injury to the Domestic Industry and whether the Anti-Dumping Duty is required to be continued or discontinued under Rule 23 (1A) of the AD Rules. Rule 23 (1A) of the AD Rules states as follows:

(1A) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

26. In MTR investigation, no separate parameters have been prescribed to examine the injury or likelihood of

injury to the Domestic Industry. Therefore, the Authority examined the injury to the domestic industry as per para (iv) of Annexure-II of the AD Rules and likelihood of continuation or recurrence considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of para (vii) of Annexure-II of the AD Rules, which states as under:

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.

(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*
- d. Inventories of the article being investigated."*

I. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

27. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including profits, return on capital employed etc. The data pertaining to performance of the domestic industry available to the Authority exhibits that the domestic industry appears not to be suffering injury in the period of investigation. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

i. Profitability and Return on capital employed

28. As per the applicant the information regarding Profit before tax, profit before interest and tax of Domestic Industry over the injury investigation period and particularly in the period of investigation is given below.

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	PBT	Rs. Lakhs	20,154	11,771	7,058	2,99,353
2	Interest	Rs. Lakhs	7,666	5,304	5,919	6,286
3	PBIT	Rs. Lakhs	27,819	17,075	12,977	3,05,639
4	Total Assets	Rs. Lakhs	4,62,044	4,21,423	4,15,470	6,13,153
5	Current Liabilities	Rs. Lakhs	1,44,849	1,18,079	1,14,405	1,50,149
6	Capital employed	Rs. Lakhs	3,17,194	3,03,344	3,01,065	4,63,004
7	ROCE	%	9	6	4	66
7a	Trend	Indexed	100	64	49	753

Source: Annual Reports of domestic producers

29. It is seen that the Profit before tax, profit before interest and tax of Domestic Industry has significantly increased during the POI as compared to the previous years as well as base year. The interest has shown a slight decreasing trend during the injury period and the POI. The total assets of the domestic industry have also increased in the POI as compared to the previous year and base year. Return on capital employed for the domestic industry has significantly improved and is as high as 66% in POI when compared to 9% in the base year.

ii. Demand-Supply Gap

30. As per the applicant the information regarding the Export Sales of the Domestic Industry for the subject goods is

as follows:

Table: Export Sales of the Domestic Industry

SN	CTH	Unit	Jan 2012-Dec 2012	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	85451100	MT		69,044	52,778	62,576	82,746
2	85451900	MT		1,836	1213	545	1,113
3		Total	74,844	70,880	53,991	63,121	83,589
4		Index		100	76	89	118

Source: Export Import Data Bank, Ministry of Commerce

31. It is seen that the demand for the subject goods has significantly increased over the injury period and the domestic sales of the domestic industry of the subject goods have also increased consistently. However, there has not been any significant increase in the capacity of the Domestic Industry. An insignificant increase in production capacities of the domestic producers compared to the significant rise in Indian demand combined with increased exports has therefore led to shortage of subject goods in the Indian market.

Table: Capacity of the Domestic Industry

SN	Company	Unit	Jan 2012-Dec 2012	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	Graphite India Ltd.	MT		80,000	80,000	80,000	80,000
2	HEG Ltd.	MT		80,000	80,000	80,000	80,000
3	Total		1,41,900	160,000	160,000	160,000	160,000

Source: Annual Reports of HEG Ltd., official website of Graphite India Ltd. and original final findings dated 19th November, 2014

32. From the above, the Authority notes that the domestic industry has an installed capacity of 1,60,000 MT and it is exporting almost 52% of its capacity despite huge demand in the Indian market. Capacity for domestic producers was 1,41,900 MT in 2012 i.e. in the POI of the original investigation and increased to 1,60,000 MT in POI of the present investigation showing 12% increase. The production capacity of domestic producers in January 2012 to December 2012 was sufficient to meet the demand in domestic market as well as for export market. However, between POI of the original investigation to the POI of the present MTR investigation, the demand for the subject goods in India has increased significantly and thus, the production capacities of domestic producers are no longer sufficient to meet the Indian demand along with exports being undertaken by them. Demand for Graphite electrodes has increased from 51,128 MT in 2012 to 1,05,066 MT in 2017 i.e., approximately 105% and it is further expected to rise to a level of 1,20,971 MT by 2019.

iii. Import volumes and Share

33. With regard to the volume of the imports, the Authority considered whether there has been a significant increase in imports, from the subject country. The Authority has therefore examined the likelihood of increase in the imports and capacities of the subject country as per Annexure II (vii) (b) which states that sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, the capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian exports. The Authority notes that Government of China PR has shut down nearly 200,000 to 3,00,000 MT per annum of electrode making capacities industrial plants on account of environmental concerns. The effect of these developments is that China PR has now become a net importer of Graphite Electrodes as against being a major exporter earlier which has seriously impacted the export volumes of the subject goods to India resulting into fall of import share. Therefore, there is no likelihood of increase in imports from the subject country. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analyzed as under:

SN	Particular	Unit	Jan 2012-Dec 2012	2015-16	2016-17	POI
1	Imports					
1a	China PR	MT	13,600	9,871	2,897	11,471
1b	Countries other than China	MT	6,240	7,348	4,073	9,460
1c	Total Import	MT	19,840	17,219	6,970	20,931
2	Market Share in Imports					
2a	China PR	%	69	57	42	55
2b	Other Countries	%	31	43	58	45

Source: Export Import Data Bank, Ministry of Commerce and original final findings dated 19th November, 2014

34. It is seen that the share of imports from China PR in total imports of the subject goods into India has declined from 69% in 2012 to 55% in POI whereas the share of imports from other countries has increased from 31% in 2012 to 45% during the POI.

iv. Rise in prices of subject goods in India

35. The Authority has examined the questionnaire responses filed by various interested parties and noted that the prices of subject goods in India have significantly increased during POI.

H. INJURY MARGIN

36. The domestic industry has not participated in the present investigation and have not submitted any data/information nor are opposing the MTR investigation, therefore, the Authority was not in a position to determine the non-injurious price.

I. SUMMARY OF VARIOUS ISSUES EXAMINED BY THE AUTHORITY CONCERNING INJURY AND LIKELIHOOD OF INJURY

37. The Authority notes that:

- No opposition by the domestic producers viz. M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd. constituting Domestic Industry in the original investigation;
- Profitability and return on capital employed of the Domestic Industry has significantly increased during the period of investigation;
- Capacities are optimally utilized by the Domestic Industry;
- Huge demand-supply gap resulted into increase in the prices of the subject goods in India;
- Reduction in export orientation from China due to shut down of 2,00,000 MT to 3,00,000 MT capacity of plants;
- Decrease in import volume and share from the subject country.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

38. The post disclosure submissions have been received from interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed in relevant paras. However, for the sake of clarity, the submissions by the interested parties are being examined as below:

Submissions made by the Domestic industry

39. No submissions have been made by the Domestic Industry in the present investigation.

Views of the Applicant and other interested parties

40. The following are the submissions made by the Applicant and other interested parties considered relevant by the Authority.

- The domestic industry has not objected to the proposed withdrawal of duty. This clearly indicates that they no longer need the protection afforded by anti-dumping duty. When the duty is no longer required by the domestic industry, its continuation only implies an additional cost burden on the importers and users of the subject goods. Thus, the duty should be withdrawn at the earliest.
- If the duty in place is terminated, it is highly unlikely that the imports from subject countries would increase so as to cause injury to the domestic industry.

- iii. Though the demand of the subject goods in India has increased by around 40%, the domestic industry has not made any efforts to increase its capacity to fulfil the demand. The demand for the subject goods is expected to increase multifold because of the increasing demand for steel, however, the domestic industry is focused on exports, it will not be able to cater to the needs of Indian local market. Further, there is a global shortage of the subject goods. The supply of the subject goods is likely be further constrained for the reason that the raw material for the subject goods, needle coke, is short in supply. In fact, both the domestic producers have in their annual reports have also acknowledged the same.
- iv. The volume of imports has reduced significantly over the injury period, the reason the imports have increased in the period of investigation is because the domestic industry was incapable to fulfill the domestic demand as their main emphasis has been on exports.
- v. The subject imports have also reduced in relation to production and consumption. the market share of imports reduced from 23% to 14% over the period.
- vi. The domestic industry's performance has improved significantly in all parameters. An analysis of the estimated figures of production and capacity utilization shows that the same have increased over the injury period. Not only have the domestic sales increased, but the market share of the domestic industry has also increased.
- vii. The domestic industry is earning profit per unit almost equal to its cost. Further, the increase in selling price is much beyond the increase in cost of the domestic industry. Thus, the prices of the goods are neither suppressed nor depressed. The significant increase in profits have led to increase in both the estimated cash profits and the return on capital employed of the domestic industry by at least 10 times.
- viii. The inventory holding period has reduced sharply from 31 days in 2014-15 to less than 10 days in period of investigation.
- ix. The interest coverage ratio shows the domestic industry has recorded significant improvement in the period of investigation. Further, the debt to asset ratio has also shown improvement, reducing from 42% in 2014-15 to falling to only 28% in the period of investigation.

Examination by the Authority

41. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs.

K. CONCLUSIONS

42. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. The imports of the subject goods from China PR in total imports into India has declined from 69% in 2012 to 55% in POI whereas the share of imports from other countries has increased from 31% in 2012 to 45% during the POI.
- ii. There is overall improvement in the health of the domestic industry. The domestic industry is not suffering from injury and the alleged dumped imports from the subject country are not resulting in material injury to the Domestic Industry.
- iii. There is an acute shortage of the subject goods in India and an insignificant increase in production capacities of the domestic producers compared to the significant rise in Indian demand combined with increased exports has led to a serious shortage of subject goods in the Indian market.
- iv. The facts of the case before the Authority do not indicate any likelihood of dumping and injury in case of cessation of AD duties.

L. RECOMMENDATION

43. The Authority notes that the mid term review investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic producers, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the mid term review investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules it is established that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti -dumping duty is removed. The Authority is of the view that imposition of antidumping duty is not warranted in the present investigation. In view thereof the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of

Anti-Dumping Duty in respect of 'Graphite Electrodes of all diameters' originating in or exported from China PR, notified vide Notification 4/2015-Customs (ADD) dated 13.2.2015.

44. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director Genl.